बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 156 ● नई दिल्ली ● शनिवार 04 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

जंग के बीच 7 दोस्त देशों को तेल भेजेगा भारत, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान

नई दिल्ली । विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का जो इस वक्त वैश्विक संकट की स्थिति के बीच पड़ोसी देशों की ओर से ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत को किए जा रहे अनुरोध पर बात कर रहे हैं। जहां रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया उन्होंने कहा कि इन सभी अनुरोधों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक ईंधन संकट के बीच भारत एक बार फिर क्षेत्र सहयोग का केंद्र बनकर उभर रहा है। जहां इस संकट के इस घड़ी में पड़ोसी देश भारत की ओर मदद के लिए देख रहे हैं। खास करके पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर और इसी मुद्दे पर जब एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने बांग्लादेश को सप्लाई किए जा रहे ईंधन से जुड़ा सवाल पूछा तो रणधीर जायसवाल ने जवाब देते हुए बताया कि भारत किन-किन पड़ोसी देशों की मदद इस संकट के समय कर रहा है .

जो डर गया, समझो मर गया.. मोदी के खिलाफ बोलने में हिचकिचाते हैं; राघव के जवाब पर आप का पलटवार

नई दिल्ली ।

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर हमला बोला है। आप ने आरोप लगाया है कि चड्ढा प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं। साथ ही आरोप लगाए हैं कि बोलने के लिए मिलने वाले समय का इस्तेमाल समोसे सस्ते कराने में लगाते हैं। आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाया है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था तो चड्ढा ने उस पर सिग्नेचर भी नहीं किए थे। पार्टी ने गुरुवार को राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाने के लिए सचिवालय को पत्र लिखा था। साथ ही पंजाब से उद्योगपति से सांसद बने अशोक मित्तल को पार्टी ने नया उपनेता नियुक्त किया है। एक्स पर एक पोस्ट में ढांडा ने जोर देकर कहा कि चड्ढा पिछले कुछ वर्षों से डरे हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हैं। आप नेता ने कहा कि पार्टी को संसद में बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इस सीमित समय में पार्टी या तो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर सकती है, या फिर हवाई अड्डे पर समोसे सस्ते करवाने की मांग कर सकती है। ढांडा ने आगे आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आप के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, जबकि जब गुजरात पुलिस आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही थी, तब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।

हम केजरीवाल के सिपाही हैं। निडरता हमारी पहली पहचान है

उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं। निडरता हमारी पहली पहचान है। अगर कोई मोदी से डरता है, तो क्या वह देश के लिए लड़ेगा? संसद में पार्टी को बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है, इस समय में हम या तो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, या फिर हवाई अड्डे की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की मांग कर सकते हैं गुजरात में, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या माननीय सांसद सदन में इस बारे में कुछ कहेंगे? पश्चिम बंगाल में वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। जब सदन में CEC के खिलाफ एक प्रस्ताव आया, तो भाई साहब ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जब पार्टी सदन से वॉकआउट कर गई, तब वे मोदी जी के लिए अपनी हाजिरी लगवाने के लिए वहीं रुके रहे।

पिछले कुछ वर्षों से तुम डरे हुए हो, राघव

ढांडा ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तुम डरे हुए हो, राघव। तुम मोदी के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते हो। तुम देश के असली मुद्दों पर बोलने से हिचकिचाते हो इससे पहले आज, राज्यसभा में पार्टी के उप-नेता पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि संसद में उनकी चुप्पी को हार नहीं समझा जाना चाहिए।

राज्यसभा में अहम मुद्दे उठाने के बजाय सॉफ्ट पीआर पर ध्यान केंद्रित किया

दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर राज्यसभा में अहम मुद्दे उठाने के बजाय सॉफ्ट पीआर पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया है। अगर कोई पार्टी लाइन से हटता है तो कार्रवाई होती है वहीं, पंजाब से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राघव चड्ढा ने पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए। अगर कोई पार्टी लाइन से हटता है तो कार्रवाई होती है। केंद्र के पंजाब के रोके गए फंड का मुद्दा नहीं उठाया। समोसे का मुद्दा उठाया।

मान ने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड का नेता बदलता रहता है। मैं भी जब संसद में था तब भी कुछ बदलाव किए गए थे। ये बदलाव होते रहते हैं। संसद में कई मुद्दे ऐसे होते हैं, जब पार्टी को वॉकआउट करना होता है लेकिन जब कोई सांसद नहीं करता है तो ये व्हिप का उल्लंघन होता है इसलिए उसके बाद कार्रवाई की जाती। मान ने कहा कि सही वोटों को काटे जाने का मुद्दा हो या गुजरात में हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, ऐसे मुद्दों को न उठाकर कैंटीन में समोसे का मुद्दा उठाया जाता है, डिलीवरी कितने समय में होगी ये मुद्दा उठाया जाता है। मुझे लगता है वो काम्प्रोमाइड हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, चड्ढा ने संसद में उन्हें बोलने से रोके जाने के पीछे के कारणों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह लगातार आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाते रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा करना किसी भी तरह की कोई गलत हरकत है। राघव चड्ढा ने कहा कि जब भी मुझे संसद में बोलने का मौका मिलता है, तो मैं जनता से जुड़े मुद्दे उठाता हूं। और शायद मैं ऐसे विषय उठाता हूं जो आमतौर पर संसद में नहीं उठाए जाते। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई अपराध किया है? क्या मैंने कोई गलती की है? क्या मैंने कुछ गलत किया है?

मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना

चड्ढा ने आगे कहा कि वह हमेशा संसद में जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं,आप सांसद ने कहा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी चुप्पी को हार नहीं समझना चाहिए। और जिन लोगों ने आज संसद में बोलने का मेरा अधिकार छीन लिया, मुझे चुप करा दिया। मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना। मेरी चुप्पी को मेरी हार मत समझना। मैं वह नदी हूं जो समय आने पर बाढ़ बन जाती है आप सांसद ने जोर देकर कहा कि संसद में उनके हस्तक्षेप रोजमर्रा की चिंताओं पर केंद्रित होते हैं, जैसे हवाई अड्डों पर खाने की यादा कीमतें, डिलीवरी कर्मचारियों को पेश आने वाली चुनौतियां, खाने में मिलावट, टोल और बैंकिंग शुल्क, कंटेंट बनाने वालों पर पड़ने वाले टैक्स के मुद्दे, और टेलीकॉम कंपनियों की ऐसी हरकतें जैसे बार-बार रिचार्ज करवाना और डेटा रोलओवर की सुविधा न देना।

राघव चड्ढा ने कहा कि मैं Zomato और Blinkit के डिलीवरी राइडर्स की समस्याओं के बारे में बात करता हूं। मैं खाने में मिलावट का मुद्दा उठाता हूं। मैं टोल प्लाज़ा और बैंक शुल्कों की लूट के बारे में बात करता हूं। मैं मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के कारण कंटेंट बनाने वालों पर पड़ने वाले असर के बारे में भी बात करता हूं। मैं इस बारे में बात करता हूं कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां हमसे 12 महीनों में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं। वे डेटा रोलओवर की सुविधा नहीं देतीं। रिचार्ज खत्म होने के बाद वे इनकमिंग कॉल भी बंद कर देती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये मुद्दे जनता के हित में हैं और सवाल उठाया कि इन्हें उठाने से पार्टी को कैसे नुकसान पहुंच सकता है। पार्टी ने बताया कि गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित किया कि अशोक कुमार मित्तल उच्च सदन में आप के नए उपनेता होंगे। मित्तल ने सदन मेंआप के उपनेता के तौर पर राघव चड्ढा की जगह ली है। राघव चड्ढा अप्रैल 2022 से सांसद भी हैं। संसद में जनहित के मुद्दे उठाने के कारण वे कई मौकों पर सुर्खियों में रहे हैं। पिछले महीने, राघव चड्ढा ने सरपंच पति या पंचायत पति की प्रथा पर चिंता जताई थी। इस प्रथा के तहत, पंचायत की आरक्षित सीटों पर चुनी गई महिलाएं अक्सर केवल नाममात्र की मुखिया होती हैं, जबकि असली सत्ता उनके पुरुष रिश्तेदार ही संभालते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधि, 73वें संविधान संशोधन के तहत परिकल्पित वास्तविक अधिकार का प्रयोग कर सकें।

बजट सत्र विस्तार पर रार - कांग्रेस बोली- संसद का दुरुपयोग कर रही सरकार, रायों में विधानसभा चुनाव की दी दलील

नई दिल्ली ।

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार इस कदम के जरिए चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। पार्टी का कहना है कि यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार महिलाओं के आरक्षण कानून और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को जल्दबाजी में लाकर चुनावी लाभ लेना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 2023 में कानून पास होने के बाद 30 महीने तक कोई कदम नहीं उठाया और अब चुनाव के समय इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।

क्या चुनावी फायदा लेने के लिए बुलाया गया सत्र?

जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का असली उद्देश्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को प्रभावित करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि

अगर यह इतना जरूरी था तो 15 दिन बाद सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। उनके मुताबिक यह कदम सीधे-सीधे राजनीतिक लाभ लेने की रणनीति है।

क्या परिसीमन से रायों का संतुलन बिगड़ेगा?

कांग्रेस ने परिसीमन को लेकर भी चिंता जताई है। रमेश ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव से छोटे रायों और दक्षिण भारत के रायों को भारी नुकसान हो सकता है। उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 120 तक जा सकती हैं, जबकि केरल जैसे रायों की संख्या बहुत कम बढ़ेगी।

क्या सरकार ने बिना जानकारी के फैसला लिया?

कांग्रेस का आरोप है कि परिसीमन को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। रमेश ने कहा कि ऑफ रिकॉर्ड जानकारी मिली है, लेकिन संसद में इस पर कोई स्पष्ट प्रस्ताव नहीं रखा गया। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

क्या विपक्ष को साथ लिए बिना बढ़ाया गया कदम?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार डिवाइड एंड रूल की नीति पर काम कर रही है और सभी दलों को साथ लेकर नहीं चलना चाहती।

क्या संसदीय प्रक्रिया का पालन हुआ?

रमेश ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस को बातचीत के लिए पत्र लिखा था, लेकिन कांग्रेस ने सभी दलों की बैठक की मांग की। इसके बावजूद सरकार ने एकतरफा निर्णय लेकर सत्र बुला लिया। राज्यसभा में इस मुद्दे पर पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो चुकी है। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार को कानून लाने का अधिकार है, जबकि विपक्ष ने इसे दबाव की राजनीति बताया।

क्या आगे और बढ़ेगा राजनीतिक विवाद?

16 अप्रैल से शुरू होने वाला यह सत्र तीन दिन तक चल सकता है। इसमें महिलाओं के आरक्षण कानून में संशोधन और लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। चुनावी माहौल में यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक टकराव बन सकता है।

पहले सरेआम चाकू से गोदकर की हत्या, फिर इंस्टाग्राम पर बनाई रील

नई दिल्ली। दिल्ली में मामूली कहासुनी के बाद युवक की सरेआम चाकू से गोदकर हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना दिल्ली के शालीमार बाग थाने की बताई जा रही है. पुलिस ने मृतक की पहचान 19 वर्षीय निक्कू के रूप में की है. हैरान करने की बात ये है कि इस हत्या को अंजाम देने के बाद एक आरोपी ने इस मर्डर की जानकारी इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड करके दी. इस रील में वो बोल रहा है कि तुम्हारे भाई ने एक मर्डर कर दिया है, तुम्हारा भाई अब कुछ दिन के अंदर जा रहा है. मैं अपने भाइयों के चक्कर में तो कुछ भी कर सकता हूं. अब मैं जा रहा हूं तिहाड़. इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने वाले आरोपी की पहचान तरुण उर्फ कर्ण के रूप में की गई है. उसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है. इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है. जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है इस घटना में करीब आधा दर्जन आरोपी शामिल थे. जिनमें से कई अभी भी फरार हैं. हालांकि, फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया है, जिनसे हत्याकांड को लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है. आपको बता दें कि दिल्ली में सरेआम हत्या करने का यह कोई पहला मामला नहीं है. कुछ महीने पहले कनॉट प्लेस में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां कुछ लोगों ने एक शख्स की सरेआम पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. पुलिस की जांच में पता चला था कि डिलीवरी करने वाले कुछ युवकों ने एक मामूली कहासुनी के बाद शिवम के सिर पर हेलमेट से बेरहमी से हमला किया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस घटना के बाद उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाजे के दौरान उसकी मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार शिवम गुप्ता की मौत 19 जनवरी को हुई है लेकिन इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अब हुई थी.पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 जनवरी की रात पीसीआर पर सूचना मिल थी कि एक शख्स कनॉट प्लेस के ई ब्लॉक में घायल हालत में पड़ा हुआ था. पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची थी शख्स की हालत बेहद खराब थी. उसे फौरन लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

राघव चड्ढा के बयान पर आप नेताओं का पलटवार, अब आतिशी बोलीं, आप मोदी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं?

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार (3 अप्रैल) को कहा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं. दरअसल, आप ने राज्यसभा उपनेता के पद से राघव चड्ढा को हटा दिया. इसके बाद उनकी ये प्रतिक्रिया सामने आई. अब आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने चड्ढा पर निशाना साधा है. दिल्ली की पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने कहा कि आप बीजेपी से इतने डरे हुए क्यों हैं?

आप बीजेपी से इतने डरे हुए क्यों हैं?

आतिशी ने कहा, आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं. राघव, आप बीजेपी से इतने डरे हुए क्यों हैं? आप बीजेपी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? आप मोदी से सवाल पूछने से क्यों डरते हैं? उन्होंने आगे कहा, आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है. आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है.

आज हमारे देश का संविधान खतरे में है. आज हमारी आंखों के सामने चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके पश्चिम बंगाल का चुनाव

छीना जा रहा है. लेकिन आप इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं. आप इस पर बोलने से डर रहे हैं.

महाभियोग प्रस्ताव पर साइन करने के मना किया

आतिशी ने आरोप लगाया, हम सभी ने देखा कि दिल्ली में वोटों की गिनती गलत तरीके से की गई. बीजेपी के अधिकारियों ने गलत वोट बनाकर चुनाव चुरा लिया. और आज यही पश्चिम बंगाल में हो रहा है. आज चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है. लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं, तब आप उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं. आम आदमी पार्टी की नेता ने महंगाई और एलपी गैस सिलेंडर के मुद्दे पर कहा, आज इस देश में, आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपी गैस सिलेंडर का है. आप एक बड़े आदमी हैं, आप राज्यसभा के सदस्य हैं. हो सकता है आपको कोई समस्या न हो. लेकिन एक आम परिवार, एक छोटा घर या कॉलोनी में रहने वाला परिवार, अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत झेल रहा है.

गैस सिलेंडर के मुद्दे पर बोलने से चुप रहे

आतिशी ने कहा, क्या आप सोच सकते हैं कि लोग काम पर जाएं या लाइन में खड़े होकर गैस सिलेंडर लें ताकि अगले दिन अपने बच्चों के लिए खाना बना सकें? जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में एलपी सिलेंडर का मुद्दा उठाया, जब सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, और जब आपको इस पर बोलने के लिए कहा गया, तब आप चुप रहे. आज इस देश में हर व्यक्ति को यह तय करना होगा कि वह मोदी के साथ है या संविधान और लोकतंत्र के साथ.

क्या आप डर के कारण लंदन चले गए थे?

आतिशी ने ये भी कहा, मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, हम सब सड़कों पर लड़ रहे थे. पुलिस हमें पीट रही थी, घसीट रही थी और हमें ले जा रही थी. हमें दिल्ली के अलग-अलग थानों में रखा गया-नरेला, बवाना. हम हर दिन सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे. जब आप लंदन में थे, आपने कहा था कि आप अपनी आंखों के ऑपरेशन के लिए गए हैं. मीडिया ने हमसे कई सवाल पूछे. हमने बार-बार कहा कि नहीं, राघव चड्ढा डरे हुए नहीं हैं. लेकिन आज मैं भी सोच रही हूं-जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब क्या आप बीजेपी से डरे हुए थे? क्या आप डर के कारण लंदन चले गए थे? राघव चड्ढा पर निशाना साधते हुए, उन्होंने कहा कि हो सकता है आप जेल जाने से डरते हों. लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं. हम न बीजेपी से डरते हैं, न मोदी से, न उनकी एजेंसियों से, न ही जेल जाने से. इसीलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे.

ट्रम्प की बेताबी

पश्चिम एशिया में चल रहा ईरान-इजराइल व अमेरिका युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा था जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे को नेस्तानाबूद करने की आवाजें लगा रहे थे मगर इसी बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा कर दी है कि वह अगले दो या तीन सप्ताहों तक इस युद्ध से बाहर आ जायेंगे, चाहे ईरान से समझौता हो या न हो। इससे लगता है कि ट्रम्प इस युद्ध में लगातार अकेले पड़ते जा रहे थे जिसकी वजह से अमेरिका में भी उनका भारी नागरिक विरोध होना शुरू हो गया है। ट्रम्प इससे पूर्व कह चुके थे कि ईरान अपने होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री रास्ते के बारे में क्या रुख अपनाता है। यह देखना अब इस रास्ते के बन्द होने से प्रभावित देशों का काम है। इससे पूर्व ईरान व इजराइल एक-दूसरे के सामरिक व महत्वपूर्ण नागरिक संस्थानों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। एक ओर जहां अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में स्थित उसके परमाणु संयन्त्र पर हमला किया तो दूसरी ओर ईरान ने इजराइल व अमेरिकी मित्र पश्चिम एशियाई देशों के तेल टैंकरों व तेल संस्थानों पर हमले शुरू कर दिये। मगर इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि यह युद्ध अब केवल दो से तीन सप्ताह ही और चलेगा और इस दौरान वह ईरान को घुटनों पर ले आयेंगे। जबकि ईरान का कहना था कि वह युद्ध विराम केवल इसी शर्त पर करेगा जब उसे यह आश्वासन दिया जायेगा कि भविष्य में उस पर कभी दुबारा हमला नहीं किया जायेगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यह युद्ध विगत 28 फरवरी को इजराइल व अमेरिका ने ही शुरू किया था जिसका प्राथमिक लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना बताया गया था। मगर ट्रम्प ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को आक्रमण के जरिये मौत के घाट उतारने के बावजूद यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके और उन्होंने युद्ध को आगे खींचते हुए इसका लक्ष्य ईरान को परमाणु शक्ति से विहीन करने का निर्धारित कर दिया परन्तु इस समर को चलते एक महीने से ज्यादा का वक्त बीतने पर इसकी जद में पश्चिम एशिया के लगभग सभी अमेरिकी मित्र खाड़ी देश भी आ गये। इन देशों की सम्पत्ति का आधार इनमें पाये जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस के स्रोत हैं और ईरान ने अपने नियन्त्रण के होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री रास्ते को बन्द करके इनके परिवहन को बन्द जैसा कर दिया जिससे दुनिया के विभिन्न देशों में ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका इस होर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री मार्ग को खोलने को एक वैश्विक मुद्दा बनाना चाहता था और विश्व के विभिन्न प्रभावित देशों को इस युद्ध में अपनी ओर करना चाहता था परन्तु इस मुद्दे पर उसे मुंह की खानी पड़ी और कई महत्वपूर्ण पश्चिमी यूरोपीय देशों ने उसके पक्ष में खड़े होने से मना कर दिया। हालांकि सभी चाहते हैं कि जलडमरूमध्य का मार्ग खुलना चाहिए लेकिन उन्होंने युद्ध में ट्रम्प का सहयोगी बनने से साफ इन्कार कर दिया। इनमें स्पेन से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली व फ्रांस तक शामिल हैं। इसके साथ ही पश्चिमी यूरोपीय देशों के सामरिक संगठन नाटो ने भी अमेरिका का साथ देने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि यह अमेरिका की अपनी लड़ाई है। इससे जाहिर था कि ट्रम्प इस मामले में धीरे-धीरे अकेले पड़ते नजर आ रहे थे जिसकी वजह से वह अब युद्ध को समाप्त करने की तजवीजें ढूंढने के लिए उतावले हुए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के बारे में अमेरिका के रक्षामन्त्री पीट हेगसेथ कह रहे थे कि अगले कुछ दिन युद्ध के लिए बहुत निर्णायक साबित होंगे। उनका कहना था कि अगर अगले कुछ दिनों में ईरान अमेरिका से समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके खिलाफ भीषण हमला किया जायेगा। इसके साथ ही ट्रम्प यह भी कह रहे थे कि यदि ईरान समझौता नहीं करता है तो उसके सभी बिजली व तेल ऊर्जा संयन्त्रों को नष्ट कर दिया जायेगा तथा उसके उस खार्ग द्वीप पर हमला करके कब्जा कर लिया जायेगा जहां से वह अपने कच्चे तेल का 90 प्रतिशत से अधिक निर्यात अन्य देशों को करता है। साथ ही ट्रम्प इस संभावना से भी इन्कार नहीं कर रहे थे कि ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों को भी उतारा जा सकता है। इसके लिए अमेरिका पश्चिम एशिया के इलाके में अपने दस हजार अतिरिक्त पैदल सैनिकों के अलावा कई नौसैनिक जहाजों को भी रवाना कर चुका था। इसका मतलब यह निकाला गया कि ट्रम्प ईरान में यह डर पैदा कर देना चाहते हैं कि अगर उसने उनकी शर्तें न मानीं तो वह पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे। मगर ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है और जवाब में इजराइल पर बेतहाशा हमले कर रहा है और अमेरिका के मित्र पश्चिम एशियाई देशों में उसके संस्थानों को भी अपने निशाने पर रख रहा है। इनमें कई खाड़ी देशों के तेल उत्पादक संयन्त्र भी शामिल हैं। अभी कल ही उसने संयुक्त अरब अमीरात के एक तेल टैंकर पर हमला किया। ईरान अब कह रहा है कि वह खाड़ी देशों में अमेरिकी कम्पनियों पर भी जवाबी हमले करेगा। दरअसल ट्रम्प कह चुके थे कि उन्हें ईरान की तेल सम्पदा पसन्द है। उनका यह कथन बताता था कि इस महायुद्ध का सबब क्या है ? क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह वेनेजुएला देश पर कब्जा करके उसकी तेल सम्पदा को कब्जाया था उससे उनके इरादे साफ हो जाने चाहिए थे। यही वजह है कि पश्चिम एशिया के इस युद्ध में यूरोपीय देशों ने अमेरिका का साथ देने से इन्कार किया और कुछ ने तो इसे असंवैधानिक युद्ध भी बताया। दरअसल ट्रम्प मूल रूप से एक व्यापारी या व्यवसायी हैं और जब किसी देश का नेतृत्व किसी व्यापारी के हाथ में पहुंच जाता है तो वह आम जनता के हितों से बेखबर हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ऐसा भारत के महान राजनीतिक दार्शनिक आचार्य चाणक्य ने अपनी कालजयी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा है। अतः हमने देखा कि ईरान-इजराइल युद्ध में सभी मानव नैतिकताएं टूटीं और सामान्य नागरिक इसका शिकार बने। इसका असली कारण यही है कि ट्रम्प की व्यापारी नजर दुनिया के विभिन्न आय स्रोतों को केवल मुनाफा कमाने की गरज से आंक रही है लेकिन उनके इस नजरिये का अब अमेरिका के नागरिकों में भी भारी विरोध होना शुरू हो गया जिसकी वजह से वह इस युद्ध से जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं।

केरल के चुनाव सभी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण

विपक्ष में एक दशक बिताने के बाद, कांग्रेस पार्टी 2026 के चुनावों से पहले केरल में अपना प्रभाव फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। सत्तारूढ़ सी.पी.आई. (एम) (माकपा) नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रयासों को तेज कर रही है। वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यू.डी.एफ. सत्ता की तलाश में है, जिसे पिछले लोकसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों के मजबूत परिणामों से बल मिला है। आगामी चुनाव एल.डी.एफ. की सत्ता बरकरार रखने की क्षमता और यू.डी.एफ. की कड़ी चुनौती का परीक्षण करेंगे। 1982 के बाद से, मतदाताओं ने हर 5 साल में बारी-बारी से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एल.डी.एफ.) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यू.डी.एफ.) का समर्थन किया है, जिससे किसी भी सरकार को लंबे समय तक सत्ता में रहने से रोका जा सका। हालांकि, 2021 में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एल.डी.एफ. ने लगातार दूसरा कार्यकाल जीता। दोनों पार्टियां वर्तमान में मोदी सरकार का विरोध और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। एन.डी.ए. केरल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भाजपा अपना वोट शेयर बढ़ाने और महत्वपूर्ण सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य स्तर पर कांग्रेस के अधिकारी आश्वस्त महसूस करते हैं। हालांकि, स्थानीय स्तर पर गंभीर समस्याएं हैं, जो भविष्य के चुनावों में उनकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा प्रमुख राजनीतिक गठबंधन है, जिसे मुख्य रूप से हिंदुओं का समर्थन प्राप्त है। इसके विपरीत, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा अल्पसंख्यक समूहों के समर्थन पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उदय ने यू.डी.एफ. से कुछ हिंदू वोटों को अपनी ओर खींचा है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आई.यू.एम.एल.) और केरल कांग्रेस शामिल है, जो लगभग 27 प्रतिशत मुस्लिमों और 18 प्रतिशत ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केरल के 6 जिलों में कम से कम दस 'स्विंग' (अनिश्चित) निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछले दो विधानसभा चुनावों में, तीनों गठबंधनों को मतदाताओं का लगभग समान समर्थन मिला था। कांग्रेस के भीतर आंतरिक संघर्ष, विशेष रूप से उम्मीदवारों के चयन को लेकर, पार्टी की एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हैं। भले ही सतीशन, चेन्निथला और वेणुगोपाल जैसे नेता विधानसभा चुनावों से पहले एकजुट दिख रहे हों लेकिन वे अभी भी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 2026 के केरल विधानसभा चुनावों में, भाजपा ईसाई मतदाताओं, विशेष रूप से मध्य केरल में, के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने, प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने प्रयासों में वरिष्ठ नेताओं को शामिल करने की योजना बना रही है। उनका लक्ष्य खुद को पारंपरिक यू.डी.एफ. गठबंधन के एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना है। पार्टी बुनियादी ढांचे, नौकरियों और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हाल ही में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) ने स्थानीय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। यह दर्शाता है कि केरल का राजनीतिक परिदृश्य, जिस पर यू.डी.एफ. और एल.डी.एफ. का दबदबा रहा है, बदल सकता है। उम्मीदवारों के चयन पर कांग्रेस के भीतर मतभेद, जिसमें टिकट वितरण के बारे में राहुल गांधी की चिंताएं भी शामिल हैं, पार्टी की एकजुटता को कमजोर और मतदाताओं के भरोसे को प्रभावित कर सकते हैं। प्रस्तावित सूची में लगभग 60 प्रतिशत उम्मीदवार लोकसभा सदस्य और पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से जुड़े हैं। गांधी ने कांग्रेस के भीतर अधिक संगठित दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। चुनाव समिति केवल राज्य इकाई के नामांकन पर निर्भर रहने की बजाय जाति समीकरण, जीतने की क्षमता और पिछले चुनावी परिणामों जैसे प्रमुख कारकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता उम्मीदवार सूची में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को लेकर भी चिंतित हैं। जमीनी स्तर पर स्थिति स्पष्ट है। माकपा ने प्रभावी प्रचार और स्पष्ट संगठन के माध्यम से मजबूत प्रगति की है। इसके विपरीत, कांग्रेस को अभी भी अपने सदस्यों को संगठित करने में कठिनाई हो रही है। कुछ लोग जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वे अपने समर्थकों के लिए टिकट सुरक्षित करने हेतु कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे केवल वफादार कार्यकर्ताओं की मदद करने या नए नेता बनाने का काम नहीं कर रहे, वे अपने समूहों को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कई शीर्ष नेता अपने वफादार समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे इसे चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने से पहले समर्थन जुटाने के तरीके के रूप में देखते हैं। सतीशन, चेन्निथला और वेणुगोपाल विधानसभा चुनावों से पहले दुर्लभ एकजुटता दिखा रहे हैं। फिर भी, राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा स्पष्ट बनी हुई है। 2026 के केरल विधानसभा चुनावों में भाजपा सक्रिय रूप से ईसाई मतदाताओं, विशेष रूप से मध्य केरल के सीरो-मालाबार समुदाय तक पहुंच रही है। स्थानीय स्तर पर जुड़कर, मुद्दा-आधारित अभियान चलाकर और नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत की सुविधा प्रदान करके, पार्टी खुद को पारंपरिक यू.डी.एफ. गठबंधन के व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है। हाल के स्थानीय निकाय चुनाव और शुरुआती सर्वेक्षण संकेत देते हैं कि यू.डी.एफ. थोड़ा आगे है लेकिन आंतरिक विभाजन का सामना कर रहा है। यदि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनावों के अपने 19 प्रतिशत वोट शेयर को बनाए रखता है, तो उसे 2021 की तुलना में 7 प्रतिशत का लाभ हो सकता है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह लाभ एल.डी.एफ. के वोटों से होगा या यू.डी.एफ. के?

ईसाई और मुस्लिम समुदाय किसे वोट देंगे? यू.डी.एफ. चुनौतियों का सामना कर रहा है। अनिश्चितता इस बात पर है कि क्या विपक्ष में एक दशक के बाद, कांग्रेस 2026 के चुनावों के लिए वापसी की पटकथा तैयार कर रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि वे (मतदाता) कांग्रेस पार्टी की ओर लौटेंगे या एल.डी.एफ. के साथ बने रहेंगे, जिसे कुछ लोग भाजपा को चुनौती देने के लिए बेहतर स्थिति में मानते हैं। इन समुदायों के प्रभाव वाली 47 सीटों के परिणाम 2026 के चुनावों का नतीजा तय कर सकते हैं।

सम्पादकीय...

'एल.पी.जी. संकट बढ़ने से कालाबाजारी तेज' सरकार को बढ़ानी होगी सख्ती!

अमरीका और इसराईल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर किए गए हमले के बाद पूरी दुनिया में पैट्रोलियम पदार्थों और गैस की किल्लत पैदा हो गई है। दरअसल ईरान ने हमले के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट आफ होर्मुज) को बंद कर दिया है। दुनिया भर को कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति का 20 प्रतिशत हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। देश में एल.पी.जी. की कमी के कारण रैस्टोरैंट कारोबार पर संकट आ गया है और देश के लगभग 10 प्रतिशत ढाबे और रैस्टोरैंट बंद हो गए हैं और कई जगह रैस्टोरैंट्स ने खाने की कीमतें बढ़ा दी हैं तथा अपने मैन्यू में आइटमें कम कर दी हैं। इसी बीच उद्योगों और ढाबों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलैंडर की कीमत बुधवार को एक बार फिर 195.50 रुपए बढ़ाई गई और दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलैंडर की कीमत अब 2078.50 रुपए हो गई है। इससे पहले, 7 मार्च को 14.2 किलोग्राम के घरेलू एल.पी.जी. के सिलैंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ाई गई थी। इसके साथ ही हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एयर टर्बाइनल फ्यूल (ए.टी.एफ.) की कीमतों में भी 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह बढ़ कर 1,04,927 रुपए प्रति किलो लीटर हो गया है। देश भर में पैदा हुई एल.पी.जी. की कमी के कारण इसकी काला बाजारी भी जोरों पर है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर घरेलू रसोई गैस का सिलैंडर 4500 रुपए में बेचा जा रहा है जबकि कमर्शियल सिलैंडर 6000 रुपए तक बिक रहे हैं। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी सुजाता शर्मा ने बताया कि एल.पी.जी. की कालाबाजारी रोकने के लिए 1 अप्रैल को लगभग 2600 छापे मारे गए और लगभग 700 सिलैंडर जब्त किए गए। इस संकट के कारण दुनिया भर में पैट्रोल, डीजल 30 से 50 प्रतिशत महंगा हो गया है लेकिन केंद्र ने पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की बजाय 27 मार्च को पैट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 10 प्रतिशत कम करके इसका बोझ सरकारी तेल कम्पनियों पर डाल दिया है। इसके साथ ही ईरान युद्ध के बाद भारत ने 40 देशों से कच्चा तेल मंगवाना शुरू किया है और इसी कारण अब होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए भारत में सिर्फ 30 प्रतिशत तेल और गैस ही भारत आ रही है जबकि युद्ध से पहले इस मार्ग से भारत 55 प्रतिशत तेल मंगवा रहा था। इसके अलावा भारत ने प्लास्टिक और दवाइयों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पैट्रोकैमिकल्स सहित 40 उत्पादों पर आयात कर में छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले से छोटे उद्योगों में लागत का दबाव कम होगा। देश भर में पैदा हुए रसोई गैस के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और 1 अप्रैल को इसी मुद्दे पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सी.सी.एस.) की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान पी.एन.जी. और एल.पी.जी. की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया, उर्वरकों की उपलब्धता का आकलन और भविष्य की रणनीति पर विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही कालाबाजारी व जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

माओवाद का खात्मा और साय सरकार की पुनर्वास नीति

माओवादी स्कूलों, रेलवे लाइनों, पुलिस थानों, डाकघरों को निशाना बनाते थे। साथ ही वे इलाके की जनता को यह समझाने में कामयाब रहे थे कि मौजूदा व्यवस्था और तंत्र सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण ही कर रहा है। चूंकि विकास की धारा इन इलाकों में माओवादी हथियारबंद दस्तों के अवरोध के चलते बह नहीं पा रही थी, इसलिए अविश्वास का माहौल बढ़ता रहा। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही एक तरफ माओवादियों को उन्हीं की तर्ज में गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ उनके पुनर्वास के साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धारा को भी बहाने की कोशिश तेज की। माओवादी कहते रहे हैं कि सत्ता की राह बंदूक की गोली से निकलती है, बारूद से निकलती है, मोदी सरकार ने कुछ उसी अंदाज में माओवादी सत्ता की राह को बंदूक और बारूद से रोका, लेकिन दूसरी तरफ पुनर्वास अभियान भी जारी रखा। इसमें राज्यों की भूमिका खास रही। चूंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, इसलिए दोनों राज्यों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिसका नतीजा सामने है। कभी पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हिंसक और माओवादी विचारधारा का असर देश के एक तिहाई हिस्से पर रहा। लेकिन अब यह विचारधारा और उसके हथियारबंद अनुयायी निस्तेज नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि वामपंथ की तरह माओवादी विचारधारा भी भारत में कुंद हो गई। नक्सली हिंसा पर लगाम इस लगाम का ही प्रतीक है। वैसे यह भी सच है कि विचारधाराएं कभी नहीं मरतीं, एक विचारधारा के रूप में वह माओवाद भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अब उसके उस तरह प्रतिबद्ध अनुयायी नहीं होंगे।

कभी देश के एक तिहाई हिस्से पर अपनी समानांतर सरकार चलाने वाली माओवादी विचारधारा का क्या आज अंत हो जाएगा? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्रीय सरकार ने आज ही के दिन को माओवादी आतंकवाद का आखिरी दिन घोषित कर रखा है। ठीक एक हफ्ते पहले यानी 25 मार्च को बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर में शीर्ष माओवादी नेता पापा राव के नेतृत्व में 18 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, तब कहा गया कि वह आखिरी महत्वपूर्ण नक्सली कमांडर है और उन्होंने भी हथियार सौंप दिए हैं। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में माओवाद पर लगाम का वादा किया था। तब झीरम घाटी कांड की याद ताजा थी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का तकरीबन समूचे शीर्ष नेतृत्व को माओवादियों ने घेरकर मार डाला था। वैसे खुद नक्सली भी मानते रहे हैं कि उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी सरकारों में खास अंतर नहीं रहा। अलबत्ता कांग्रेस सरकार माओवादी हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाने से बचती रही है, जिस तरह बीजेपी की अगुआई वाली सरकारें उठाती रही हैं। बस्तर में छह अप्रैल 2010 को बारूदी सुरंगों के जरिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों को उड़ाने के बाद नक्सलियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी गुस्सा था। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने माओवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का मन बना लिया था, लेकिन सिविल सोसायटी के दबाव में यह विचार उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन बीजेपी ने माओवादियों को कोई रियायत नहीं दी। 2019 में गृहमंत्रालय की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने खुलेआम नक्सलियों को चेतावनी देनी शुरू कर दी कि या तो वे हथियार डालें या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही उन्होंने 31 मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा से देश को मुक्त करने का ऐलान कर दिया। जिस तरह शीर्ष नक्सली कमांडर या तो मारे गए हैं या फिर उन्होंने हथियार डाले हैं, उससे लगता है कि बीजेपी सरकार का अपना वादा पूरा करने जा रही है। माओवादी विचारधारा के प्रभाव में घर-परिवार, सुख-चैन छोड़कर जंगलों की खाक छानने और सत्ता से जूझने वाले माओवादी युवाओं को मुख्यधारा में लाने में सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों का दबाव ही काम नहीं आया, बल्कि इसमें राज्यों की पुनर्वास योजनाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ ने 2025-26 की अपनी पुनर्वास नीति में हिंसा छोड़ने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें उसका पूना मारगेम अभियान प्रमुख रहा। इन शब्दों का अर्थ है नया रास्ता'। इसके तहत दंडकारण्य क्षेत्र के सैकड़ों माओवादी कैडरों को मुख्यधारा में वापस लाने की सफल कोशिश हुई। इसके तहत नक्सलियों की वापसी के बाद उन्हें नई जिंदगी शुरू करने के लिए तत्काल डेढ़ लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी गई, साथ ही उन्हें तीन साल के लिए मासिक वजीफा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना शुरू हुआ। मकसद यह रहा कि हथियार छोड़ने के बाद मुख्यधारा में लौटे माओवादी आत्मनिर्भर जिंदगी बिता सकें। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने हथियार सौंपने वाले माओवादियों को अलग से प्रोत्साहन राशि देने की भी व्यवस्था की। इससे राज्य में माओवादियों के समर्पण में तेजी आई। हथियार छोड़ने वाले माओवादियों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया गया, इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित आवास भी मुहैया कराए गए। इसके साथ ही उन्हें वापसी के बाद भयमुक्त जीवन गुजारने के लिए परिवार की सुरक्षा की गारंटी भी दी गई। इसी तरह झारखंड सरकार ने भी माओवादियों को समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति बनाई। जिसके तहत समर्पण के बाद माओवादियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। उनके कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन्हें रोजगार के साथ ही आवास की व्यवस्था की जाती है। साथ ही उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। झारखंड की इस नीति का उद्देश्य समर्पित नक्सलियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत हथियार जमा करने पर पूर्व नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि, उन्हें तत्काल पुनर्वास अनुदान और घरेलू सामान के लिए नकद सहायता दी जाती है। साथ ही उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे भविष्य में अपना रोजगार कर सकें। इसके साथ ही उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा व छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जाती है। उन्हें आवास के लिए भूमि या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए जाते हैं। इसी तरह मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों को खेती के लिए प्राथमिकता के आधार पर सोलर पंप और बिजली कनेक्शन भी देने का इंतजाम है। पूर्व नक्सलियों पर चल रहे छोटे मामलों को झारखंड सरकार जहां वापस ले रही है, वहीं गंभीर मामलों में कानूनी सहायता मुहैया करा रही है। कुछ ऐसे ही इंतजाम पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में किए गए हैं।

कभी माओवादियों के डर से बस्तर में सड़कें तक बनाना संभव नहीं था, बिजली पहुंचाना भी कठिन था। झारखंड के भी दुमका के इलाके में ऐसा ही हाल था। लेकिन केंद्र सरकार की शह पर राज्य सरकार ने नक्सली हिंसा प्रभावित क्षेत्र में भी सड़क, स्कूल और अस्पतालों का निर्माण कराने में तेजी आई। बस्तर के कुछ इलाके में रेलवे लाइन भी पहुंच गई है। नक्सली इलाके में सड़कें भी बेहतर हो गई हैं। इन कदमों से माओवादी प्रभाव में रहने वाले इलाकों में भरोसा बहाली में मदद मिली। सरकारी योजनाओं के साथ ही सरकार के प्रति भी स्थानीय लोगों का रवैया बदला। कभी पशुपति से तिरुपति यानी नेपाल से आंध्र तक का जंगली इलाका लाल गलियारे के रूप में विख्यात था। यहां सुरक्षा बलों के लिए भी घुसना आसान नहीं था। इसमें देश के तकरीबन एक तिहाई जिले आते थे। इन जिलों में माओवादी वैचारिकी के असर वाले हथियारबंद दस्तों की सत्ता चलती थी। माओवादी स्कूलों, रेलवे लाइनों, पुलिस थानों, डाकघरों को निशाना बनाते थे। साथ ही वे इलाके की जनता को यह समझाने में कामयाब रहे थे कि मौजूदा व्यवस्था और तंत्र सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण ही कर रहा है। चूंकि विकास की धारा इन इलाकों में माओवादी हथियारबंद दस्तों के अवरोध के चलते बह नहीं पा रही थी, इसलिए अविश्वास का माहौल बढ़ता रहा। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही एक तरफ माओवादियों को उन्हीं की तर्ज में गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया, वहीं दूसरी तरफ उनके पुनर्वास के साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की धारा को भी बहाने की कोशिश तेज की। माओवादी कहते रहे हैं कि सत्ता की राह बंदूक की गोली से निकलती है, बारूद से निकलती है, मोदी सरकार ने कुछ उसी अंदाज में माओवादी सत्ता की राह को बंदूक और बारूद से रोका, लेकिन दूसरी तरफ पुनर्वास अभियान भी जारी रखा। इसमें राज्यों की भूमिका खास रही। चूंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं, इसलिए दोनों राज्यों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। जिसका नतीजा सामने है। कभी पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हिंसक और माओवादी विचारधारा का असर देश के एक तिहाई हिस्से पर रहा। लेकिन अब यह विचारधारा और उसके हथियारबंद अनुयायी निस्तेज नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि वामपंथ की तरह माओवादी विचारधारा भी भारत में कुंद हो गई।

नक्सली हिंसा पर लगाम इस लगाम का ही प्रतीक है। वैसे यह भी सच है कि विचारधाराएं कभी नहीं मरतीं, एक विचारधारा के रूप में वह माओवाद भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अब उसके उस तरह प्रतिबद्ध अनुयायी नहीं होंगे, उनकी गोलियों की आवाज और धमक भी नहीं होगी। अगर यह विचारधारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े तो शायद ही किसी को एतराज होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर यह विचारधारा जिंदा भी बचती है तो वह लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ेगी, हथियारों के दम पर नहीं।

भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं, सामाजिक विश्वास का हनन

वैश्विक स्तरपर भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र सदियों से अतिथि देवो भव रहा है, जिसने न केवल सामाजिक मूल्यों को आकार दिया,बल्कि भारत की वैश्विक पहचान भी स्थापित की।किंतु आज के परिवर्तित समय में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस मंत्र को एक व्यापक और अधिक समकालीन रूप देते हुए, नागरिक देवो भव के रूप में स्थापित किया जाए। यह केवल एक नारा नहीं,बल्कि शासन व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन का दर्शन है। जब तक शासन के केंद्र में नागरिक नहीं होगा,तब तक विकास की कोई भी परिकल्पना अधूरी ही रहेगी। यह मंत्र केवल एक नारा नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था के मूल चरित्र में आमूल-चूल परिवर्तन का आह्वान है। 2 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा कर्मयोगी साधना सप्ताह के दौरान दिया गया संदेश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।वर्तमान समय में जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में 2047 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है तब भ्रष्टाचार इस यात्रा का सबसे बड़ा अवरोध बनकर सामने आता है।इसलिए यह समय की मांग है कि जैसे नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए समय सीमा 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया,वैसे ही भ्रष्टाचार के समूल नाश के लिए भी एक ठोस और समयबद्ध रणनीति अपनाई जाए। जिसकी मांग मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हर आर्टिकल के माध्यम से करते रहता हूं आज फिर इस आर्टिकल के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध नहीं है,यह सामाजिक विश्वास का हनन है। यह उस तंत्र को खोखला करता है, जिसपर लोकतंत्र टिका होता है। विकसित भारत के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध यदि हम ईमानदारी से आत्ममंथन करें,तो पाएंगे कि भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार है। यह केवल आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाता, बल्कि सामाजिक विश्वास, प्रशासनिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी कमजोर करता है।भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है, जो व्यवस्था को भीतर से खोखला कर देती है। चाहे वह एक छोटे स्तर का कर्मचारी हो या उच्च पदस्थ अधिकारी जब तक काम निकलने की मानसिकता और जुगाड़ संस्कृति समाज में बनी रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार का पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं।जब एक आम नागरिक सरकारी दफ्तर में जाता है,तो वह केवल एक सेवा की अपेक्षा नहीं करता,बल्कि वह न्याय,पारदर्शिता और सम्मान की भी उम्मीद करता है। यदि उसे वहां भ्रष्टाचार,उपेक्षा या अपमान का सामना करना पड़ता है,तो उसका विश्वास न केवल उस संस्था से,बल्कि पूरे शासन तंत्र से उठने लगता है।यही कारण है कि नागरिक देवो भव की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है,क्योंकि यह शासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित करती है कि नागरिक सर्वोपरि है और उसकी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है। साथियों बात अगर हम नागरिक देवो भव की संकल्पना को समझने की करें तो इसका का अर्थ है,हर नागरिक को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।यह सोच प्रशासन को पावर-सेंट्रिक से पीपल-सेंट्रिक बनाती है।इस अवधारणा के अंतर्गत सरकारी पद केवल अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनता है,अधिकारी और कर्मचारी अपने रुतबे को त्यागकर सेवाभाव को अपनाते हैं, हर निर्णय में नागरिक के हित को सर्वोपरि रखा जाता है।यदि चपरासी से लेकर मंत्री तक हर व्यक्ति इस भावना को आत्मसात कर ले, तो भ्रष्टाचार का स्वतः ही अंत हो सकता है।व्यक्तिगत परिवर्तन से संस्थागत परिवर्तन तक पीएम ने अपने संबोधन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही हमारा व्यक्तिगत परिवर्तन ही संस्थागत परिवर्तन का आधार बन सकता है।यह विचार अत्यंत गहरा है। जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होता है, तो उसका प्रभाव पूरे संस्थान पर पड़ता है।एक ईमानदार क्लर्क पूरी फाइल प्रक्रिया को पारदर्शी बना सकता है,एक जिम्मेदार अधिकारी पूरे विभाग की कार्यशैली बदल सकता है।एक संवेदनशील मंत्री नीति निर्माण को जनहितकारी बना सकता है।इस प्रकार,इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ही इंस्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बनता है।स्थानीय प्रशासन सरकार का वास्तविक चेहरा आम नागरिक के लिए सरकार का मतलब संसद या मंत्रालय नहीं होता, बल्कि उसका स्थानीय सरकारी कार्यालय ही सरकार का चेहरा होता है।तहसील कार्यालय नगर निगम,पुलिस स्टेशन,सरकारी अस्पताल यही वे स्थान हैं, जहां नागरिक सीधे सरकार से जुड़ता है। यदि यहां का व्यवहार सकारात्मक, पारदर्शी और संवेदनशील होगा, तो लोकतंत्र में विश्वास स्वतः ही मजबूत होगा। लेकिन यदि यहां भ्रष्टाचार, देरी और असंवेदनशीलता होगी, तो जनता का विश्वास डगमगा जाएगा।कर्तव्य- प्रधान प्रशासन- अधिकार से अधिक जिम्मेदारीपीएम ने प्रशासनिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, अधिकार से अधिक कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना।भारतीय संविधान भी यही सिखाता है कि अधिकार, कर्तव्यों के निर्वहन से ही प्राप्त होते हैं।जब कोई अधिकारी हर निर्णय से पहले यह सोचता है कि यह निर्णय जनता के लिए कितना लाभकारी है? इससे कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा? तो उसके निर्णय स्वतः ही अधिक प्रभावी और सटीक रूप से अति जनहितकारी बन जाते हैं। साथियों बात अगर हरशासकीय कर्मचारी द्वारा इस भाव की संकल्पना को समझने की करें तो,हम आज आवश्यकता है कि चपरासी से लेकर उच्चतम अधिकारी तक,मंत्री से लेकर मंत्री तक,हर शासकीय कर्मचारी इस भावना को अपने भीतर आत्मसात करे। पद का अहंकार छोड़कर सेवा का भाव अपनाना ही इस परिवर्तन की कुंजी है। जब एक अधिकारी अपने पद को अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखेगा, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा।यह व्यक्तिगत परिवर्तन ही संस्थागत परिवर्तन का आधार बनता है। यदि हर व्यक्ति यह सोचने लगे कि उसके एक निर्णय से कितने लोगों का जीवन प्रभावित होगा,तो वह निर्णय अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी होगा। साथियों बात अगर हम वर्तमान समय में भारत को करें तो, भारत एक आकांक्षी समाज के रूप में उभर रहा है, जहां हर नागरिक के अपने सपने हैं, अपने लक्ष्य हैं। इन सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी केवल नागरिक की नहीं, बल्कि पूरे शासन तंत्र की भी है। जब सरकार और नागरिक के बीच विश्वास का संबंध मजबूत होता है, तभी विकास की गति तेज होती है।इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यवस्था अधिकसंवेदनशील उत्तरदायी और पारदर्शी बने। नागरिक देवो भव का सिद्धांत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शासन को नागरिक- केंद्रित बनाता है।इस संदर्भ में क्षमता निर्माण आयोग (कैपेसिटी बिल्डिंग कमिशन) और आईगॉट मिशन कर्मयोगी जैसी पहलें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनका उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं है,बल्कि एक नई कार्यसंस्कृति का निर्माण करना है, जहां हर सरकारी कर्मचारी एक कर्मयोगी के रूप में कार्य करे। कर्मयोगी वह होता है,जो अपने कर्तव्य को पूजा मानता है और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। जब यह भावना प्रशासन में विकसित होती है,तो वह केवल कार्य निष्पादन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनती है।प्रशासनिक सुधारों के लिए यह भी आवश्यक है कि विभागों के बीच समन्वय और संवाद को बढ़ावा दिया जाए। अक्सर देखा जाता है कि विभिन्न विभागों के बीच संवादहीनता के कारण योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पातीं। इससे न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि नागरिकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यदि सभी विभाग एक साझा दृष्टिकोण और समझ के साथ कार्य करें, तो शासन अधिक प्रभावी और सटीक रूप से परिणामोन्मुखी बन सकता है। साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति को समझने की करें तो, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है,बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना भी आवश्यक है।इसके लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र, पारदर्शी प्रक्रिया और समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है। यदि किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच वर्षों तक लंबित रहती है, तो यह न केवल न्याय में देरी है,बल्कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मामले की जांच के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/[illegible])

स्कूली बच्चों के पोषण पर सरकार का खास ध्यान

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 747 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य के स्कूली बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही यह एक प्रमुख योजना है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की उच्च स्तरीय बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में योजना के वर्तमान क्रियान्वयन, वित्तीय प्रगति तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना की भी व्यापक समीक्षा की गई। स्वीकृत बजट में केंद्र सरकार का 222 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार का 525 करोड़ रुपये का हिस्सा है। मुख्य सचिव श्री रस्तोगी ने सभी जिलों में गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जिला और विद्यालय स्तर पर निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिया जाने वाला भोजन पौष्टिक, स्वादिष्ट और निर्धारित मानकों के अनुरूप् हो, इसके लिए नियमित निरीक्षण के साथ-साथ विद्यार्थियों से भी फीडबैक लिया जाए। बैठक में धनराशि के प्रभावी उपयोग और समय पर किस्त जारी करने संबंधी उपायों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मौलिक शिक्षा निदेशक सुश्री मनीता मलिक ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में बाल वाटिका से लेकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक के 14.8 लाख से अधिक बच्चों को योजना के तहत शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। यह योजना स्कूली बच्चों को आहार उपलब्ध करवाने, सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने और विद्यार्थियों का नामांकन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति ने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन मेन्यू और पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की भी समीक्षा की, जिनमें दूध, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, मूंगफली पिन्नी और खीर जैसे पूरक पोषण तत्व शामिल हैं। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय सिंह दहिया, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री शेखर विद्यार्थी, विभिन्न विभागों से समिति सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

16 से 30 अप्रैल तक जिलावासी पोर्टल पर कर सकेंगे स्वः जनगणना

सोनीपत।

-06 अप्रैल से जिला में दिया जाएगा जनगणना स्टाफ को प्रशिक्षण
-लघु सचिवालय में डीसी की अध्यक्षता में जनगणना प्रशिक्षण को लेकर बैठक का हुआ आयोजन

6 अप्रैल से जिला में जनगणना स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे जनगणना का कार्य सुचारू व व्यवस्थित ढ़ग से किया जा सके। शुक्रवार को उपायुक्त नेहा सिंह की अध्यक्षता में जनगणना प्रशिक्षण को लेकर लघु सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य आगामी प्रशिक्षण को लेकर रूपरेखा तैयार कर कार्य करना व प्रभारी अधिकारियों व फील्ड ट्रेनरों को दिए गए प्रशिक्षण की समीक्षा करना रहा है। उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है। जिसके माध्यम से जनसंख्या से संबंधित सटीक आंकड़े एकत्रित किए जाते है। उन्होंने बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जियो टैगिंग, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन व अन्य सभी कार्य जल्द से जल्द करे, जिससे जनगणना के कार्य को समय पर किया जा सके। सहायक निदेशक ओमप्रकाश ने बताया कि जिला में 6 अप्रैल से जनगणना स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी अपने क्षेत्र से संबंधित जनगणना के कार्य को सरलता से कर सके। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक http://se.census.gov.in/ पोर्टल पर नागरिक स्वःजनगणना भी कर सकते है। जिला जनगणना समन्वयक अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि वर्ष 2027 की जनगणना भारत की प्रथम डिजिटल मोड में आयोजित होनी वाली जनगणना होगी। इसमें मोबाइल एप व सीएमएमएस पोर्टल के माध्यम से डेटा का संकलन किया जाएगा। इस मौके पर जेसी एमसी मीतू धनखड़, सीटीएम सिमरन, डीआरओ सुशील शर्मा, सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार व अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

शहरों में आबादी अनुसार नई जल निकासी परियोजनाओं के प्रस्ताव किए जाएं तैयार - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी ड्रेनों, नहरों एवं नालों की सफाई का कार्य बरसात से पहले पूरा किया जाए। विशेषकर आबादी क्षेत्र में ड्रेन एवं नहरों के साथ मजबूत बर्म बनाएं जाएं और कार्य की नियमित रूप से मोनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री शुक्रवार को सिंचाई, जनस्वास्थ्य एवं स्थानीय निकायों विभाग के अधिकारियों के साथ ड्रेन, नहरें एवं नालों की सफाई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहाबाद में राजस्थान सीमा तक बरसाती पानी की निकासी हेतु ड्रेन का प्रस्ताव बनाया जाए ताकि उस पानी का क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए उपयोग कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है। पानी का बहाव आबादी क्षेत्रों में अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए जलभराव की स्थिति बन जाती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए नई जल निकासी परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जाएं ताकि भविष्य में उन क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति न बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसाती एवं जल निकासी संबंधित ड्रेन एवं नहरों की सफाई कार्य को तत्परता से पूरा करवाएं और इस कार्य में कोई लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में तटबंध कमजोर हो और टूटने के कगार पर हो उनका समय से पूर्व निरीक्षण कर मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा निचले क्षेत्रों में भी तटबंधों को मजबूत करें ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी ओवरफ्लो न हो सके। इसके अलावा इन तटबंधों को पर्यावरण की दृष्टि से हरा भरा बनाने के लिए पेड़ लगाए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि घग्गर, मारकण्डा, टांगरी नदी की सफाई के साथ तटबंधों पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा कुरूक्षेत्र में चीका के पास सरस्वती नदी के बहाव को सीधा किया जाए। उन्होंने बावल में इंडस्ट्री के पानी की निकासी हेतू भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि अब तक विभिन्न 825 ड्रेन एवं नालों के कार्यों में से 713 पर कार्य कर लिया गया है। शेष पर आगामी जून माह तक कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म बाढ बचाव 425 कार्यों में से 250 कार्यों के टेंडर फाइनल कर दिए गए हैं तथा शेष के लिए माह के अंत तक पूरे कर लिए जाएगें। इसके अलावा विभाग में जल निकासी हेतू 1678 क्यूसेक क्षमता के 839 डीजल पम्प, 4466 क्यूसिक क्षमता के 1389 इलेक्ट्रिक पम्प तथा 3465 क्षमता के 495 मोबाईल पम्प तैयार हैं। इस प्रकार प्रदेश में 9609 क्यूसेक क्षमता के 2723 पम्प तैयार कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 87 स्थानीय निकायों में 2655 किलोमीटर लम्बाई की 2382 ड्रेनों में से 1116 किलोमीटर लंबी ड्रेनों की सफाई की कार्य कर लिया गया है।

शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत लिया दो बार परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय

चंडीगढ़ ।

सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी/ गुरूकुल विद्यापीठ के परीक्षार्थी 04 अप्रैल से कर सकेंगें आवेदन

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत सैकेण्डरी/ सीनियर सैकेण्डरी (नियमित) एवं गुरूकुल/विद्यापीठ (पूर्व मध्यमा सह माध्यमिक/उत्तर मध्यमा सह वरिष्ठ माध्यमिक) की दो बार परीक्षा आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक परीक्षार्थी 04 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 तक द्वितीय परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि सैकेण्डरी एवं सीनियर वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2026 का समापन हो चुका है। ऐसे सभी नियमित परीक्षार्थी जो वार्षिक परीक्षा फरवरी/मार्च-2026 में प्रविष्ट हुए हैं लेकिन अपनी दी गई परीक्षा से संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे परीक्षार्थियों को शिक्षा बोर्ड द्वारा अंक सुधार का मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक परीक्षार्थी अतिरिक्त विषय को छोड़कर अधिकतम किन्हीं भी 03 विषयों की पुन- परीक्षा देने के लिए स्वयंपाठी तौर पर 1000/- रूपये शुल्क सहित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 04 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बोर्ड प्रवक्ता ने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त जो परीक्षार्थी अपरिहार्य कारणों जैसे गंभीर बीमारी/चोट/खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता इत्यादि परिस्थितियों के कारण वार्षिक परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हो पाए, ऐसे सभी परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय में निर्धारित तिथियों में संपर्क करते हुए निर्धारित शुल्क ऑफलाइन व पात्रता संबंधित दस्तावेज जमा करवाकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यदि कोई परीक्षार्थी प्रथम वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों की परीक्षा में अनुपस्थित रहा है और पुन- परीक्षा हेतु आवेदन करता है तो ऐसे परीक्षार्थी का आवेदन पत्र अयोग्य मानते हुए रद्द किया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि बारे परीक्षार्थियों को शीघ्र ही सूचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हैल्पलाईन नंबर 01664-254300 पर संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा में भवन नक्शा पास करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बनाई जाने वाली घरेलू एवं वाणिज्यिक इमारतों के लिए नगर निकाय विभाग से पास होने वाले नक्शों की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को भी सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा। उन्होंने इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी सचिवालय में शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अर्बन चैलेंज फंड को लेकर भी अधिकारियों से अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की। जिसके तहत अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को इस योजना के तहत हरियाणा में किए जाने वाले कार्य की योजना बारे पहलुओं को साझा किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग (रीयूज) को लेकर भी गंभीरता से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहरों में स्थापित एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से निकलने वाले पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस पानी को पार्कों की सिंचाई, उद्योगों तथा कृषि कार्यों में प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री, पार्क और खेती में इस ट्रीटेड पानी का प्रभावी उपयोग हो सके। बकायदा यह भी कहा गया कि एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) से पार्क तक अथवा जहां पानी का इस्तेमाल होना है, वहां लंबी अवधि तक चलने वाले पाइप लाइन भी बिछाए जाएं। पार्क, ग्रीन बेल्ट में तो इसे लेकर व्यवस्था करने पर खासा फोकस किया जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हरियाणा में भविष्य में जो भी नए एसटीपी स्थापित किए जाएंगे, उनमें रियूज वाटर सिस्टम का प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग हो। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मौजूदा सीवरेज व्यवस्था के संबंध में विस्तृत डेटा तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आंकलन किया जाए कि किन-किन क्षेत्रों में

कब और किस जनसंख्या के आधार पर सीवरेज सिस्टम डाला गया था। वर्तमान समय में कई क्षेत्रों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है, जो कुछ स्थानों पर तीन गुना तक पहुंच चुकी है। ऐसे में भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई रूपरेखा तैयार करना अत्यंत आवश्यक है।

कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि विकसित भारत की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कार्यों में देरी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने नगर निकाय विभाग के सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि टेंडर अलॉट होने के बाद कार्य लंबे समय तक लंबित न रहे। ठेकेदारों को पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करना होगा। यदि आवश्यकता हो तो अधिक मैनपावर, साधन और मशीनरी लगाकर कार्य में तेजी लाई जाए, ताकि समय अवधि को कम किया जा सके।

सड़कों की संभाल पर खास फोक्स रहे

बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 16 हजार किलोमीटर सड़कों की जीआईएस मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। 'म्हारी सड़क' ऐप के माध्यम से इन सड़कों से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने

कार्यों में देरी स्वीकार नहीं - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
वेस्ट वाटर रियूज सिस्टम को किया जाए मजबूत
2,276 सड़कों की पहचान कर मरम्मत करने की दिशा में नगर निकाय विभाग ने उठाए कदम

के लिए जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को बेहतर और सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि विभाग के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के विभिन्न निकाय क्षेत्रों में कुल 2,276 सड़कों की पहचान की गई है। इनमें से 1,144 सड़कों का निर्माण 510.34 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इन सड़कों में कुछ ऐसी कच्ची सड़कें भी शामिल हैं, जो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आती थीं, लेकिन अब नगर निगम सीमा में शामिल हो चुकी हैं। इसी प्रकार 1,083 सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 591.51 किलोमीटर होगी और इस पर 594.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। इसके अतिरिक्त 49 सड़कों को पैचवर्क के लिए चिन्हित किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 18.25 किलोमीटर है और इन पर 10.33 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विकास कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे हों, ताकि आमजन को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मिशन निदेशक श्री शाश्वत सांगवान भी मौजूद थे।

थिनर से एक्सपायरी डेट मिटा बेच दे रहे थे खाने-पीने का सामान, पुलिस ने किया भंडाफोड़, 3 को दबोचा

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है. राजधानी के द्वारका इलाके में 'एक्सपायर हो चुके खाद्य और पेय पदार्थों की दोबारा पैकेजिंग कर उन्हें बाजार में बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है. इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को दबोचा भी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी नामी ब्रांड्स के एक्सपायर या एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स की तारीख में हेरफेर कर उन्हें दोबारा बिक्री के लिए भेज रहे थे. दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में बताया कि यह कार्रवाई को जहांगीर ब्रांच की टीम की तरफ से की गई है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने विभिन्न ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स के 3,096 डिब्बे बरामद किए. इसके अलावा, जाने-माने ब्रांड्स के बिस्किट की भी बड़ी खेप जब्त की गई, जिनकी पैकेजिंग और स्टिकर में बदलाव किया गया था. पुलिस के अनुसार, यह सामान दोबारा बाजार में खपाने की तैयारी में रखा गया था. जहांगीर ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदोरा ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया. आरोपियों ने बताया कि वे बाजार से एक्सपायर या एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट्स को पहले खरीदते थे, फिर थिनर की मदद से उनकी मैन्युफैक्चरिंग

और एक्सपायरी डेट मिटा दी जाती थी. इसके बाद मशीन का इस्तेमाल कर पैकेटों पर नई तारीख प्रिंट कर दी जाती थी. पुलिस के अनुसार, बदली हुई तारीख वाले प्रोडक्ट्स को डिब्बों में दोबारा पैक किया जाता था. इसके बाद इन्हें बाजार में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता था, जिससे ग्राहकों की सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो सकता था. इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक, 29 मार्च को सूचना मिली थी कि द्वारका के बामनोली गांव में कुछ लोग एक अवैध यूनिट चला रहे हैं. जहां मल्टी ब्रांड्स के 'एक्सपायर हो चुके या जल्द एक्सपायर होने वाले खाद्य और पेय पदार्थों की तिथियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी. सूचना में बताया गया था कि बदली हुई तारीख के साथ इनको दोबारा बाजार में बेचा जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने द्वारका के सेक्टर-28 स्थित एक गोदाम पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में शीतल पेय और पैकेट बंद खाद्य पदार्थ पाए गए. शुरुआती जांच में सामने आया कि इन उत्पादों की पैकेजिंग से छेड़छाड़ की गई थी. मौके से बरामद सामान को तुरंत कब्जे में ले लिया गया. छापेमारी के समय गोदाम में मौजूद शिवम सिंह और लोकेश कुमार को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया कि वे इस अवैध इकाई के मालिक कमल मुदगिल के निर्देशों पर काम कर रहे थे. कुछ ही देर बाद कमल मुदगिल भी मौके पर पहुंचा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

अमेरिका और ईरान के बीच और तेज हुई जंग, पायलट की तलाश में गए यूएस हेलिकॉप्टर को भी मार गिराया

नई दिल्ली। अपने पायलटों की तलाश में ईरान के ऊपर सर्च ऑपरेशन चला रहे अमेरिका के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने की खबर है. इसको लेकर ईरानी मीडिया ने बताया है कि अमेरिकी सेना मध्य ईरान में तलाशी और बचाव अभियान चलाने की कोशिश कर रही है. नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को जानकारी देते हुए इस खबर की पुष्टि भी की है. यह हमला एक प्रोजेक्टाइल से हुआ है. अमेरिकी सेना ने ईरान में अपने एक पायलट को बचा लिया है. इससे पहले खबर आई थी कि ईरान और अमेरिका में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं. अमेरिका ने लापता पायलटों की तलाश तेज कर दी थी. अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के अंदर युद्धस्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. अमेरिकी एयरक्राफ्ट सर्च ऑपरेशन के दौरान बेहद ही निचले

स्तर पर उड़ान भरते हुए पायलट की तलाश में जुटे हुए हैं. इससे यह ऑपरेशन संवेदनशील और जोखिम भरा माना जा रहा था. रिपोर्ट्स में सामने आया है कि घटनास्थल पर पायलट की इजेक्शन सीट जमीन पर ही मिली थी. कुछ देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया था कि अमेरिकी आर्मी के जवान ईरान पहुंचकर सर्च अभियान और बचाव में लग गई है. इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के एफ-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया. इसके अलावा एफ-15E को भी ईरान ने निशाना बनाया. ईरान की

पायलटों की तलाश में ईरान के ऊपर सर्च ऑपरेशन चला रहे अमेरिका के एक लड़ाकू विमान को मार गिराने की खबर है. अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी देते हुए इस खबर की पुष्टी भी की है.

सरकारी मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि एफ-35 विमान सेंट्रल ईरान में गिराया गया था. उसके पायलट के बचने की संभावना बेहद कम है, हालांकि, अमेरिका ने अपने एक पायलट का रेस्क्यू सफलतापूर्वक कर लिया है. इसके अलावा अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के पायलट को जिंदा पकड़ लिया, उसे बंधक बना लिया. हालांकि, इन दावों की किसी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी थी. इधर, ईरान के एक बड़े पुल को नष्ट करने के बाद ट्रंप ने नागरिक सुविधाओं और बिजली संयंत्रों पर हमले करने का संकल्प लिया है. ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताते हुए पलटवार किया है. वहीं, कुवैत ने कहा है कि ईरान ने एक वॉटर प्लांट को निशाना बनाया है. साथ ही एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया. वहीं, अन्य खाड़ी देशों को हमलों का सामना करना पड़ रहा है. इधर, ईरान ने कुवैत के दावों को नकार दिया है. ईरान ने शुक्रवार को इजरायल पर भी मिसाइल हमले किए हैं. ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ईरान से जीत की घोषणा करने की अपील करते हुए इसको समाप्त करने को कहा है. अब तक इस युद्ध में कम से कम 2,076 लोग मारे गए हैं. इनमें 26,500 घायल हुए हैं.

दिल्ली समेत उत्तर भारत में महसूस हुए भूकंप के झटके, 5.9 रही तीव्रता

दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की रात भूकंप के झटके महसूस हुए। इससे लोग डर के घरों के बाहर आ गए। भूकंप के झटके पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता 5.9 रही। जम्मू-कश्मीर के एक अधिकारी ने बताया कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 150 किलोमीटर अंदर था। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में था। भूकंप के झटके चार देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदुकुश था। गाजियाबाद के एक स्थानीय निवासी का कहना है, जब हमने भूकंप महसूस किया, तब बारिश हो रही थी। यह कोई बड़ा भूकंप नहीं था। फिर मैं स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर आया। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स है, जो लगातार घूमती रहती है। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती है, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते है। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किमी के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा।

मालदा में हाल ही में हुई घटना एक सोची समझी साजिश थी - मुख्यमंत्री ममता

***भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप**

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गरमाता जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मालदा में हाल ही में हुई घटना एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका उद्देश्य राज्य में अशांति फैलाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। हाजरीपाड़ा मैदान में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया, मालदा की घटना की जांच सीआईडी कर रही है। लोगों को मुंबई से लाया गया था और पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी। जहां एनआईए, उन्हें पकड़ने में नाकाम रही, वहीं हमारी सीआईडी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, यह घटना उस समय हुई जब बड़ी संख्या में लोग चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि करीब 1.20 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं या हटाने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तबादलों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि 506 अधिकारियों के ट्रांसफर में से 483 केवल बंगाल से हैं, जिसमें डीजीपी और मुख्य सचिव जैसे अहम पद भी शामिल हैं। ममता बनर्जी ने मतदाताओं, खासकर महिलाओं से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि मतदान के दिन झाड़ू लेकर निकलें और वोट के जरिए जवाब दें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों, खासकर सीआरपीएफ, का इस्तेमाल बीजेपी के पक्ष में किया जा सकता है।

स्वदेशी पनडुब्बी से बढ़ी नौसेना की ताकत, रक्षा मंत्री बोले- अरिदमन शब्द नहीं शक्ति!

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को नौसेना में शामिल किया, जिससे भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में सिंह ने कहा कि यह शामिल होना हमारी नौसेना की शक्ति, मूल्यों और प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। रक्षा मंत्री ने नौसेना की निरंतर उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारी नौसेना, चाहे फारस की खाड़ी हो या मलक्का जलडमरूमध्य, हिंद महासागर में निरंतर अपनी उपस्थिति बनाए रखती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे वह बचाव अभियान हो या मानवीय सहायता प्रदान करना, हमारी नौसेना हमेशा सबसे आगे रहती है। हमारी नौसेना भारत के मूल्यों और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी के शामिल होने से हमारी नौसेना की शक्ति, मूल्य और प्रतिबद्धता और भी मजबूत होगी। सिंह ने आगे कहा कि आज अत्याधुनिक युद्धपोत 'तारागिरी' को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। तारागिरी का शामिल होना भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और भारतीय नौसेना सहित सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए समुद्री शक्ति के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की बात करते है, तो उस परिकल्पना में नौसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा वाला हमारा देश, जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, समुद्र के बिना अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकता। हमारे लगभग 95 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा भी समुद्र पर निर्भर करती है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि एक मजबूत और सक्षम नौसेना हमारे लिए केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। भारत की परिचालन तत्परता पर सिंह ने कहा कि जब भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, भारतीय नौसेना ने हमारे वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपने नागरिकों और व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए विश्व स्तर पर हर संभव कदम उठा सकती है।

राहुल गांधी को है हार का शतक लगाने की जल्दी- केशव मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें अपनी हार का शतक लगाने की जल्दबाजी है, असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत उनकी इस ख्वाहिश जरूर पूरा करेगी। गांधी द्वारा असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा पर की गई टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है। केशव मौर्य ने सोशल मीडिया पर कहा कि असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर ओछी टिप्पणी कर राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि उनका सांसद के तौर पर पांच बार और एक बार लोकसभा में विपक्ष के नेता का अनुभव कुंठा से लबालब है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को तो छोड़िए, गांधी संवैधानिक पद पर बैठे किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भी किसी क्षण अपमानित कर सकते है। उन्होंने कहा कि वे यह नहीं जानते कि हिमंता बिस्वा सरमा पर उनकी ओछी टिप्पणी समूचे उत्तर-पूर्वी राज्यों का अपमान है। राहुल गांधी को अपनी हार का शतक लगाने की जल्दबाजी है, असम में भाजपा की जीत उनकी ख्वाहिश जरूर पूरा करेगी।

ईरान की मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज उड़ाने की धमकी लिस्ट जारी की

तेल अवीव। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम मानता है, क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की लिस्ट में कुवैत,यूएई , सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण पुल शामिल हैं। इनमें शेख जाबेर अल-अहमद समुद्री पुल (कुवैत), शेख जायद ब्रिज, अल मकता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, किंग फहद कॉजवे (सऊदी अरब-बहरीन) और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दून ब्रिज शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के करज शहर में B1 ब्रिज पर दो बार हमला किया था।

तेहरान के पूर्व मंत्री ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की दी सलाह

खुद की जीत घोषित कर, जंग खत्म कर दे ईरान

तेल अवीव। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध और खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच एक और अहम खबर सामने आई है. ईरान के पूर्व मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि तेहरान खुद को विजेता घोषित करके सीजफायर कर दे. उन्होंने ईरान को अमेरिका के साथ डील करने की भी सलाह दी है. युद्ध का शुक्रवार (3 मार्च) को 35वां दिन है, लेकिन अभी तक यह थमता नजर नहीं आ रहा है. जवाद जरीफ ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध नहीं रोक पा रहे हैं तो ईरान को ही रोक देना चाहिए, लेकिन पहले खुद की जीत की घोषणा कर देनी चाहिए. उन्होंने यह कहा कि ईरान को एक ऐसा समझौता करना चाहिए, जिससे जंग रुक जाए और भविष्य में भी किसी तरह की दिक्कत न हो. हालांकि ईरान फिलहाल जंग रोकने की दिशा में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है.

हॉर्मुज को लेकर क्या बोले जरीफ

ईरान ने युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक लगा दी है. ईरान के मंत्री ने कहा है कि तेहरान को हॉर्मुज खोलने का ऑफर देकर अमेरिका से डील करनी चाहिए और खुद पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटवा लेना चाहिए.

ईरान के लिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप

ट्रंप ईरान युद्ध को अलग स्तर पर पहुंचाने की तैयारी में हैं. वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए यूरेनियम हासिल करना चाहता है. ट्रंप ने अधिकारियों से इसके लिए प्लान बनाने को कहा था, जो कि अब पेश भी कर दिया गया है. इस ऑपरेशन के लिए हजारों कमांडो की जरूरत पड़ सकती है. जमीन पर उतर कर एयरस्ट्रिप बनानी पड़ेगी, भारी उपकरणों को पहुंचाना होगा. जमीन के नीचे छिपे यूरेनियम को निकालने में भी बड़ी चुनौती होगी. इस ऑपरेशन में हफ्तों लग सकते हैं.

अप्रैल में मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव, दिल्ली-हरियाणा में बारिश तो जम्मू-कश्मीर में गिरेंगे ओले

नई दिल्ली। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही उत्तर एवं पश्चिम भारत में मौसम के मिजाज में उतार-चढ़ाव है। इस हफ्ते दो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण देश के लगभग आधे हिस्से में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पूरे महीने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के संकेत दिए हैं। मौसम में दो-तीन दिन सूखा और उसके बाद फिर दो-तीन दिन बारिश जैसा पैटर्न दिख सकता है।

इन राज्यों पर दिखेगा असर

मौसम विज्ञानियों के अनुसार, पहला पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है, जिसका असर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभों की यह सक्रियता

हिमालयी क्षेत्र में लगातार नमी ला रही है। यही कारण है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बार-बार मौसम बदल रहा है। पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रणाली के कारण भारी वर्षा दर्ज की गई है, जिससे संकेत मिलता है कि यह सिस्टम अभी और सक्रिय रह सकता है। शनिवार को बड़े क्षेत्र में तेज हवा और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कश्मीर घाटी में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और ओलावृष्टि की भी संभावना है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सात-आठ अप्रैल के आसपास सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में फिर से मौसम बदलेगा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना अधिक है। राजस्थान के कई हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है।

फिर बढ़ेगा तापमान

इस दौरान तापमान सामान्य से नीचे या उसके आसपास रहने की संभावना है। गर्मी की तीव्रता फिलहाल थमी रहेगी। हालांकि, पांच अप्रैल को एक ब्रेक देखने को मिलेगा, जब उत्तर और पश्चिम भारत में ठंडी और शुष्क हवाएं चलेंगी। इससे मौसम साफ होगा और तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। मध्य भारत में भी इस प्रणाली का असर स्पष्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर कोंकण क्षेत्र तक गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है।

दुष्कर्म के आरोपी खरात की कॉल कनेक्शन पर सियासत गरम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 17 कॉल का दावा

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब एक स्वयंभू से जुड़े कॉल डिटेल रिकॉर्ड को लेकर बड़े आरोप सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने दावा किया कि दुष्कर्म के आरोपी अशोक खरात और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच 17 बार फोन पर बातचीत हुई। इस दावे ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अंजलि दमानिया के मुताबिक, उन्हें व्हाट्सऐप के जरिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है। इसमें कई नेताओं और गॉडमैन के बीच बातचीत का जिक्र है। उन्होंने दावा किया कि शिंदे और खरात के बीच सबसे लंबी बातचीत 21 मिनट की थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये कॉल किस समय अवधि में हुए। इस मामले में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने संपर्क क्यों थे।

क्या शिंदे और खरात के बीच 17 कॉल हुए?

दमानिया ने आरोप लगाया कि सीडीआर के अनुसार शिंदे और अशोक खरात के बीच कुल 17 कॉल हुए। यह दावा राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि खरात पर गंभीर आपराधिक आरोप है। हालांकि सरकार की ओर से इन कॉल्स को लेकर कोई गैरकानूनी बात होने से इनकार किया गया है।

क्या अन्य नेताओं के नाम भी सामने आए?

दमानिया ने यह भी कहा कि सिर्फ शिंदे ही नहीं, बल्कि भाजपा और एनसीपी के कई नेताओं ने भी खरात से बातचीत की थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल और एनसीपी नेता सुनील तटकरे के साथ भी आठ-आठ कॉल हुए। इसके अलावा भाजपा मंत्री आशीष शेलार

के साथ भी संपर्क का जिक्र किया गया।

क्या रुपाली चाकणकर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है?

दमानिया के अनुसार, एनसीपी नेता रुपाली चाकणकर और खरात के बीच 177 कॉल हुए थे। यह सबसे ज्यादा बातचीत का मामला बताया गया। इस खुलासे के बाद चाकणकर ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें खरात के कथित अपराधों की जानकारी नहीं थी। सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है। मंत्री उदय सामंत और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि किसी को फोन करना या मिलना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अपराध तभी माना जाएगा जब किसी की सीधी संलिप्तता साबित हो।

शिवसेना ने भी कहा कि खरात जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

आरोपी अशोक खरात पर क्या आरोप लगे?

महिलाओं को झांसा देकर बुलाना यौन शोषण के आरोप काला जादू कानून के तहत केस

अंजलि दमानिया ने यह भी बताया कि उन्होंने सीडीआर की कॉपी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस महानिदेशक और एसआईटी को भेज दी है।

अशोक खरात को मार्च में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ अब तक 8 एफआईआर दर्ज हैं। उस पर एक महिला के साथ तीन साल तक दुष्कर्म करने का आरोप है। अब यह मामला जांच के दायरे में है और आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं।